Study on Handicrafts

1080. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government have undertaken any study on the different kind of handicrafts made in Rajasthan and Orissa which are popular in International markets;

(b) if so, the details of the study made in that regard; and

(c) the steps taken or purposed to be taken by Government to promote and popularise these handicrafts in different countries?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) and (b) Yes, Sir. Government constantly reviews the export performance and potential of different categories of handicrafts popular in the international market, including those from Rajasthan and Orissa. Some of the studies of Rajasthan & Orissa Handicrafts undertaken in the post covered tie and dye, woollen carpet, ivory carving, hand-woven textiles, marble work, lac bangle, handicrafts of Puri silver, filigree craft of Cuttack and horn industry. More recently, a project for documentation of stone crafts of India including Rajasthan and Orissa have been sanctioned to the Crafts Council of India and two projects for survey of folk art and Saurya Painting of Orissa were sanctioned to the Crafts Council of Orissa and a report on the Economic Status of Handicrafts artisans including those from these two states, commissioned through the National Council of Applied Economic Research.

(c) The steps taken to promote and popularise handicrafts including those from Rajasthan and Orissa in different countries include:

(i) Seminars to educate local exporters of Marble Hindicrafts, hand printed textiles and made ups thereof, India items etc.

(ii) Export publicity campaign, participation in fairs, trade delegations, buyer seller meets and exhibitions through the Export Promotion Council for Handicrafts and Carpet Export Promotion Council etc.

(iii) Exposure of the handicrafts of Rajasthan and Orissa through catalogues brought out by the Rajasthan Small Industries Corporation of India Ltd. and the Orissa State Co-operative Handicrafts Corporation Ltd. and through brochures of the Export Promotion Council for Handicrafts and commercial promotion and activities of the Handicrafts and Handlooms Export Corporation.

(iv) Training Programme to acquaint exporters with export procedures and documentation.

हाथ करघा बनकरों के लिए योजना

1081. श्री विनोद शर्मा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 मई, 1992 को "दि स्टेट्समैन" में "इकोनोमिक कंडीशन अनचेंज्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार द्वारा हथकरघा उद्योग में कार्यरत बुनकरों के लिए अनेक सुविधाओं की घोषणा किए जाने के बावजूद उन्हें इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल सका है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच करने तथा बुनकरों के लाभ के लिए विकल्पों का सुझाव देने हेतु कोई समिति गठित की है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां ।

(ख) आठवीं योजना के दौरान सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों की कवरेज बढ़ाने के लिए वर्तमान योजनाओं में संशोधन किया है और नई योजनायें आरंभ की गई हैं । इसके अतिरिक्त योजनाओं को पुनः तैयार किया गया है और नई योजनाएं इस प्रकार तैयार की गई हैं ताकि सहकारी क्षेत्र में शामिल न किए गए बुनकरों को भी उनका लाभ मिल सके ।

(ग) सरकार ने सातवीं योजना के दौरान कार्यान्वित योजनाओं का मूल्यांकन करने और आठवीं योजना में इनका कार्यान्वयन करने/इन योजनाओं में संशोधन आदि के लिए सुझाव देने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

हथकरघा बुनकरों को सहकारी समितियों के रूप में संगठित किया जाना

1082. **श्री विनोद शर्मा** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हथकरघा उद्योग में कार्यरत बुनकर देश भर में बिखरे हुए हैं और उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि केवल 30 प्रतिशत बुनकर ही सहकारी समितियां बना कर संगठित हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन बुनकरों के असंगठित होने के कारण इन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश के बुनकरों को संगठित करने तथा उन्हें सहकारिता आन्दोलन के अंतर्गत लाने के लिए कोई योजना तैयार की है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) हथकरघा बुनाई एक घरेलू कार्यकलाप है और अधिकांश बुनकर ग्रामों में रहते हैं । इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ही हथकरघा क्षेत्र के विकास की योजनायें तैयार की गई हैं ।

(ख) वर्ष 1987-88 में की गई हथकरघा गणना के अनुसार 20.29 प्रतिशत हथकरघा बुनकरों को सहकारी क्षेत्र में लाया गया है तथा 4.15% बुनकर राज्य हथकरघा विकास निगम, खादी और ग्रामोद्योग आयोग और खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड के अंतर्गत लाए गए हैं ।

(ग) सरकार द्वारा चलाई जा रही कुछ योजनायें सभी बुनकरों के लिए उपलब्ध हैं चाहे वे सहकारी क्षेत्र में हों अथवा उससे बाहर । ऐसी योजनाओं में बुनकर सेवा केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षण, डिजाइन आदि की आपूर्ति शामिल है । थ्रिफ्ट फंड योजना जो सातवीं योजना के दौरान केवल सहकारी क्षेत्र के बुनकरों के लिए ही उपलब्ध थी, में संशोधन किया गया है ताकि सहकारी क्षेत्र से बाहर के बुनकरों को भी इसका लाभ मिल सके और यह छूट 1991-92 से उपलब्ध है । वर्ष 1992-93 में लागू की गई समूह बीमा योजना सहकारी और गैर-सहकारी क्षेत्र के बुनकरों के लिए उपलब्ध है । 1991-92 में आरंभ की गई प्रोजेक्ट पैकेज योजना भी सहकारी क्षेत्र से बाहर के बुनकरों को उपलब्ध है । इसी प्रकार कार्यशाला-सह-आवास योजना भी सहकारी क्षेत्र से बाहर के बुनकरों को उपलब्ध है ।

(घ) तथापि सरकार सहकारी क्षेत्र से बाहर के बुनकरों को भी इन योजनाओं का लाभ दे रही है लेकिन हथकरघा बुनकरों को सहकारी क्षेत्र में लाने के प्रयत्न जारी हैं । प्राथमिक हथकरघा सहकारी समितियों का सदस्य बनने के लिए हथकरघा बुनकरों को ऋण सहायता देने की सातवीं योजना में जारी योजना 1992-93 में भी जारी है । वर्ष 1991-92 में आरंभ और चालू वर्ष में भी लागू निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी